Creation of an All India Education Service

1439. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the progress made so far in the matter of creation of an All India Education Service;

(b) which are the States that have opted for this Service; and

(c) what is the objection if any, thereto of the other States?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (c) The National Policy on Education—1986 has laid down:—"A proper management structure in education will entail the establishment of the Indian Education Service as an All-India Service. It will bring a national perspective to this vital sector. The basic principles, functions and procedures of recruitment to this service will be decided in consultation with the State Governments".

The details are being worked out.

महारानी लक्ष्मी बाई के किले का अधिग्रहण किया जाना

1440. **डा० गोविन्द दास रिछारिया :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने रक्षा मंत्रालय से वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई के किले का अधिग्रहण कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और किले का अधिग्रहण कब तक कर लिए जाने की सभावना है ; और

(ग) किले को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखत है ?

शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) झांसी स्थित किले को राष्ट्रीय महत्व के एक स्मारक के रूप में घोषित किए जाने के लिए कदम उठाने के अतिरिक्त इसके संरक्षण और भू-दृश्य निर्माण का एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ।

नई शिक्षा नीति क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

1441. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा कितनी और किस प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) इस नई शिक्षा नीति द्वारा निरक्षरता की दर किस सीमा तक कम होने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत किसी अन्य राज्य की तरह, बिहार को भी दी जाने वाली वित्तीय सहायता अलग-अलग योजनाओं पर निर्भर होगी । राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय कार्यवाही योजना तैयार कर रहा है । कार्यवाही योजना के यथा अनुमोदन के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में योजनाएं यथासमय विकसित की जायेंगी ।

(ख) निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रमों में सभी आयु वर्ग के निरक्षरों को शामिल किये जाने की परिकल्पना की गयी है । देश में साक्षरता दर का पता 1991 में तब चलेगा जब जनगणना आयोजित की जायेगी । अगली दो पंच वर्षीय योजनाओं की

अवधि के दौरान निरक्षरता दर में काफी कमी होने की सम्भावना है ।

मोतियाबिन्द के कारण अन्धता

1442. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मोतियाबिन्द के कारण आंखों की रोशनी खो देने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आंखों के कितने आपरेशन किये जाते हैं, पिछले वर्ष आंखों के कितने आपरेशन किए गए थे और उनमें से कितनों को आंखों की रोशनी वापस मिल गई थी तथा कितनों की आंखों की रोशनी इस आपरेशन के कारण चली गई थी ; और

(ख) अंधता को रोकने के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 1971 73 में किए गये एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अनुमानित कुल 90 लाख दृष्टिहीन व्यक्तियों में मोतियाबिन्द के कारण दृष्टिहीन हुए व्यक्तियों की संख्या लगभग 55 प्रतिशत बैठती है । पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गये आपरेशनों की संख्या नीचे दी गई है :—

1983–84 . . .	10.69 लाख
1984–85 . . .	11.34 लाख
1985–86 . . .	11.39 लाख

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 1985 में मोतियाबिन्द के आपरेशनों के बाद बिहार में तीन व्यक्तियों ने नेत्रों की रोशनी खो दी ।

(ख) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में शुरू किया गया था । निम्नलिखित उपाय सोचे गये हैं :—

1. नेत्र शिविरों का आयोजन करके ग्रामीण नेत्र-रोग उपाय करना ।

2. स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा देने के उपायों को तेज करने के साथ-साथ चरणबद्ध ढंग से परिधीय, मामले तथा केन्द्रीय स्तरों पर नेत्र परिचर्या सेवाओं का विकास करना । छठी योजना के अन्त तक 80 केन्द्रीय तथा 30 जिला मोबाइल यूनिटें चालू करने के अलावा 2000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 404 जिला अस्पतालों तथा 60 मेडीकल कालेजों में यह कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है ।

Financial assistance for AIDS to Tamil Nadu

1443. SHRI M. VINCENT: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have created any separate agency on the lines of I.C.M.R. to investigate and confirm suspected cases of AIDS; and

(b) if so, the number of confirmed AIDS patients who are under surveillance and what provisions have been made by Government of Tamil Nadu State by way of financial and technical assistance to make such investigations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) The Government have not created any separate agency on the lines of Indian Council of Medical Research to investigate and confirm suspected cases of AIDS. However, 12 diagnostic centres for detection of AIDS have been set up, In addition, 4 referral centres have also been established where higher level diagnostic facilities for AIDS are available.

(b) Upto 15-7-86, 19 confirmed cases of AIDS infection have been detected in the country as under:—

Andhra Pradesh . . .	1
Tamil Nadu	15
Kerala	1
Maharashtra	2